

प्रेषक,

आर० डी० पालीवाल,  
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड ।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 18 दिसम्बर, 2007

विषय-नामिका अधिवक्ताओं की आबद्धता बढ़ाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में वर्तमान में सहायक अभियोजन अधिकारियों के पदों के विरुद्ध आबद्ध नामिका अधिवक्ताओं का कार्यकाल उनके कार्यकाल की समाप्ति की तिथि से (चाहे कार्यकाल पूर्व में समाप्त हो चुका हो अथवा भविष्य में समाप्त होने वाला हो) दिनांक 31.3.2008 तक बढ़ाये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, परन्तु राज्य सरकार किसी भी समय बिना कोई कारण बताये एवं बिना किसी पूर्व सूचना के किसी नामिका अधिवक्ता की आबद्धता समाप्त कर सकती है ।

2- कृपया तदनुसार अपने-अपने जिलों में कार्यरत नामिका अधिवक्ताओं को सूचित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,


( आर० डी० पालीवाल )  
सचिव,

संख्या-609 (1)/XXXVI(1)/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन ।
- 2- महानिदेशक, अभियोजन उत्तराखण्ड, देहरादून
- 3- समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड ।
- 4- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 5- गार्ड फाईल/एन.आई. सी. ।

आज्ञा से,

  
(आलोक कुमार वर्मा)  
अपर सचिव ।